THE DEPUTY CHAIRMAN: No. I am going ahead. *(Interruptions)...}Ao.* There was no time given. *(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU: He has actually misled the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then you can go to the Privileges Committee. If he has misled the House, please make a privilege issue and send it to us. We will examine it. *(Interruptions)...*

The question is:

That the Bill further to amend the Food Corporations Act, 1964, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill. Clause I, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री शांता कुमार **:** मैं प्रस्ताव करता हूं **:**
"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

The question was put and the motion was adopted.

THE SUGARCANE CONTROL (ADDITIONAL POWERS) REPEAL BILL, 2000

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : महोदया, "मैं प्रस्ताव करता हूं"-

"कि गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शाक्तियां) अधिनियम , 1962 का निरसन करने वाले विधयेक पर विचार किया गया ।"

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The motion is moved. I have got only three names. Shri Santosh Bagrodia

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान) : महोदया, अभी हम लोगों ने गेंहूं और चावल की बात की...

उपसभापति : अब मीठी बात करिए ।

श्री संतोष बागड़ोदिया : अब हम लोग उसको मीठा कैसे किया जाए इसकी बात करेंगे। I Madam, Deputy Chairperson, I rise to support this Sugarcane Control (Additional Powers) Repeal Bill, 2000. This Bill, like other Bills, needs to be repealed because, in real terms, there are too many laws on different subjects in the country. So, 1 think the Government is rightly repealing this. When we are talking about sugar, the most important factor which I want to discus^ about the sugar industry is...

THE DEPUTY CHAIRMAN; No, no. I am sorry, I am going to be very strict about the rules of the House. The Bill is placed before you. But you cannot discuss the problems of the entire sugar industry, because, then, the hon. Minister will not be able to answer. Besides, the House also presents a bad picture because the Bill...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam, I will confine myself to the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. I am not going to listen to anything. You are not restricting yourself to the-Bill. You just said that you were going to discuss it. 1 must say whatever is the ambit of the Bill, you please speak within that. Because, otherwise, the discussion becomes irrelevant. Answers do not come. Once a thing has been discussed in the House, the Business Advisory Committee may take a decision. So, it has already been discussed. Let us not discuss all that. Because, then, we will not be able to discuss the matters which are very important. So, please stick just to the repeal of the Bill and not on the sugar...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam, I am going to restrict myself to the Sugarcane Control (Additional Powers) Repeal Bill, 2000. Do you want me to restrict myself to it?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, 1 want you to restrict yourself to it.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Okay Madam. I will restrict myself to it. Madam, as we are talking about the sugarcane control order, I would say that, nowadays, there is an infonnation appearing in the newspapers that Government is planning to stop this system of monthly release of sugar. The whole purpose of this monthly release in a poor country like India was; this is

a seasonal industry. The entire sugar is produced in four or five months. If the entire quantity is released in one go, it will be impossible to get enough buyers and the result will be that there will be a complete flood in the market. If this process is adopted, then the mills will be closed. As you have seen, despite this scheme being in force, despite this scheme continuing, what is happening in Gulbarga? The farmers in Gulbarga district are actually destroying their sugarcane crop in the fields itself In fact, the Karnataka Government even allowed them to take it to Bombay or Goa, because there were no buyers. If you are going to stop this mechanism, I want to tell the Hon. Minister, through you Madam, that the entire industry will be completely destroyed. I am for liberalisation in general. Even in this case I am for liberalisation. But please first introduce the mechanism of forward trading. First introduce that method. Once the forward trading is introduced, then slowly you can stop this system also. You can release more quantity. Because, at the moment, we have plenty of production in our country. As we are talking about this release method, if I show you the figures Mr. Minister, in 1994 our production was 146 lakh tonnes. After that, our production was 164 lakh tonnes. Despite that so much import has come, of which you are very much aware. This import was made as late as in 1998-99. So, this kind of irresponsible import by the Government or due to the Government policies is creating immense problems for the sugar industry.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) in the Chair]

When I see the figures, I do not understand the rationale behind it. Every year you had a stock. At the end of the year 1994-95, there was a stock of 54.95 lakh tonnes. In 1995-96, the closing stock of sugar was 79.07 lakh tonnes. The total need of the country is 141 lakh tonnes. That means 50 per cent of the total need of the country was a carry forward stock. But still we went on importing. We imported it in 1998-99. 1 do not know what the reasons were. Sir, if we go into the details of duty structure, during this period there was zero duty when there was need for the import of sugar. I can understand that. But what has happened after that? They imposed a duty of five per cent. Then it was increased to 20 per cent. Then it was increased to 40 per cent which has further been increased to 60 per cent. 3अब 60 परसेंट ड्यूटी लगाने के बाद भी, जैसी मुझे खबर है डब्ल्यू.टी.ओ. मे आप डेढ़ सौ करोड़ ड्यूटी भी लगा सकतें हैं। आज के दिन इंपोर्ट बंद हो गया होगा, लेकिन लोगों की इच्छा जो हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया, ज्यों-ज्यों आपने ड्यूटी बढ़ाई त्यों-त्यों उन्होनें अपने रेट

कम कर दिए । वैसे ही सारे वर्ल्ड में, ब्राजील वगैरह में 40 लाख टन एक दिन में एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, जबकि हिन्दुस्तान में भी भी ऐसी यूनिट्स हैं जो साढ़े सात सौ,हजार टन की यूनिट्स है, वे उनसे कैसे कंपीट करेंगी ? इसलिए उस एंगल को देखते हुए मेरा अनुरोध हैं िक डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार अगर डेढ़ सौ परसेंट तक जा सकतें हैं, आप इतनी ड्यूटी लगाइये कि इंपोर्ट तो न हो और एक्सपोर्ट करने का रास्ता निकालें । उसके लिए अगर आवश्यकता हो तो 20 परसेंट आप एक्सपोर्ट बैनिफिट दीजिए । हमारे पास सरप्लस स्टॉक है और अगर ज्यादा नहीं, जितना आप समझते हैं जिससे िक शुगर की आवश्यकता हिन्दुस्तान में कम न हो या शुगरकी आवश्यकता के अनुसार चीनी न रहे, ऐसी व्यवस्था न बने, उसको ध्यान में रखते हुए आप लिमिटेड एक्सपोर्ट करने के बारे में विचार करिए । आप एस.डी.एफ. का क्या कर रहें हैं ? ग्यारह हजार करोड़ रूपया एसीडीएफ का आपके पास पड़ा हुआ है, इसमें आपने ऐसा नियम बना दिया है कि बैंक गांरटी मिलेगी तभी आप देंगे । बैंक गांरटी अब मिलती नहीं । जब बैंक गारंटी नहीं मिलती तो वह रूपया पड़ा रहेगा । अब कोई प्रैक्टिकल नियम बनाइए । ऐसा कुछ रास्ता निकालिए कि रूपया आपके पास जो पड़ा हुआ है वह इंडस्ट्री के काम आए और इंडस्ट्री के काम आएगा तो फार्मर के काम आएगा और जब यह नियम है कि आपको पता है कि वाइस चेयरमैने सर, यह मालूम है चीनी एक महीने, दो महीने, तीन महीने में नहीं बिक सकती, जो चीनी आज बनती है साल भर के बाद इनका रिलीज़ आर्डर आता है, साल भर के बाद बिकता है और उसके कारण फार्मर को पैसा नहीं मिल पाता । बैंकों को भी अब छूट मिल गई है । वे शुगर मिल्स को रूपया नहीं देते जबकि शुगर ऐसी चीज़ है जो हंडरेड परसेंट इसके बैंकों के ताले के भीतर रह करके पैसा देते हैं । आप कुछ ऐसा नियम बनाइये कि बैंको को यह जो इंडस्ट्री है जिसमें फार्मर्ज इन्वाल्वड है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं, इसमें बैंकर्ज के ऊपर यह नियम लागू किया जाए कि शुगर इंडस्ट्री को जितने रूपये की आवश्यकता हो वह अपना 15 परसेंट, 20 परसेंट, 25 परसेंट, जो भी उनका नियम हो, वह मार्जिन रख कर रूपया दे, जिससे िक फार्मर को पैसा मिले । नहीं तो हो क्या रहा है कि फार्मर को पैसा मिलता नहीं मिल वालों को उनको तो माल देना ही पड़ता है कमांड एरिया के हिसाब से और वह रूपया 6 महीना, 12 महीना लेट मिलता है, न उनका ब्याज़ मिलता है और फार्मर मर जाता है । इसका कुछ रास्ता अगर आप निकला सकतें हैं, तो मेरी समझ में इंडस्ट्री का भी भला होगा और फार्मर का भी भला होगा । अभी गत महीने की बात है, जब पार्लियामेंट का सैशन नहीं था, अभी आज के जो हमारे मंत्री महोदय हैं, उन्होनें बहुत अच्छा काम किया है, सारा एलोकेशन कंप्यूटराइज्ड कर दिया । कोई गड़बड़ नहीं हो सकती । सब को नियम के अनुसार मिलेगा । पता नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर

आफिस से, अखबारों में मैनें पढा कि 5िमलों को ऐलोकेशन दिया गया। मलासकपुर शुगर मिल को 4500 टन, मोदीनगर को 5000 टन, रेणुका सागर 1000 टन पर मंथ, जे.एच.पी. शुगर, यू.पी, 1000 टन पर मंथ और गिरधारी लाल शुगर मिल को 1000 टन पर मंथ का एलोकेशन किया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि इन मामलों को ये स्पेशल एलोंकेशन क्यों किया गया। केवल इन 5 मिलों को इस तरह शुगर क्यो रिलीज किया गया ? मंत्री महोदय, कृपया इस बारे में ध्यान दें या इक्विलेंट क्वांटिटी सभी को अलाउ कर दें। मंत्री महोदय, ने इस सिस्टम को एक्विटेबल किया था, वह बहुत अच्छा सिस्टम था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा किया गया ? सुना है कि पी.एम. ऑफिस मे कुछ लोंगों के प्रभाव में आकर पॉलिटिकल रीज़न से ऐसा किया गया है। इसे कृपया देखा जाए और ऐसा डिस्टिक्रमिनेशन न हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अंतिम बात यह है कि एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है- चाहे वह शुगर हो या चाहे और दूसरी इंडस्ट्रीज हों। उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे टैक्सटाइल मंत्री जी ने प्लास्टिक बैग में पैकिंग अलाउ कर दी है । ठीक है, इस से शुगर इंडस्ट्री को कुछ लाभ हो जाएगा। फिर इन्होनें अलाउ किया 10 परसेंट लेकिन शुगर इंडस्ट्री नेजितनी आवश्यकता थी , सभी में प्लास्टिक पैंकिंग चालू कर दी। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस से शुगर में प्लास्टिक का जो जहर जाएगा, उस की जिम्मेदारी किस की होगी ? तो यह 5 परसेंट, 10 परसेंट या 15 परसेंट की बात तो जनता और इंडस्ट्री दोनों को बेवकूफ बनाने की बात है। आप जूट इंडस्ट्री को तो मारेंगे ही, शुगर भी नहीं बचेगी क्योकि शुगर के टेडर्स ने उस के दाम गिरा दिए और कहा कि आप कम पैसे में बोरा लेतें हैं, इस से शुगर के दाम गिर गए । तो उपसभाध्यक्ष महोदय, इस से फायदा किस का हुआ, ट्रेडर्स का हुआ। इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस संबंध में टैक्सटाइल मंत्री से बात करें और जिस तरह से जूट बेग्स में पैकिग हो रहा था, वही साइंटिफिक, एनवायरमेंटल और खाने वालों के लिए अच्छी बात है।

महोदय, यह बिल पास हो जाए, लेकिन मैं ने जो अनुरोध किया है, अगर मंत्री जी उस तरफ ध्यान देंगे तो उस से देश का भी भला होगा और उन की सरकार का भी भला होगा। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please remember that this Bill, which we are trying to repeal, was meant to help the Sugarcane Control Order, which itself, stands repealed. So, this Bill has become redundant So, we will confine ourselves to the discussion on the

repeal itself and not go into the finer aspects of production, distribution, etc., of suger.

Mr. Margabandu may also will kinely remember this.

SHRI R. MARGABANDU(Tamil Nadu): Sir, I rise to oppose this Bill, in the Statement of Objects and Reasons, it is given that the Sugarcane Control (Additional Powers) Act, 1962 was enacted to empower the Central Government to amend the Sugarcane Control Order, 1955, with retrospective effect. So, this is the reason. Since, the 1955 Act itself was repealed and was substituted by the Sugarcane Control Order, 1966, it becomes redundant and it is unnecessary, here, 1 would like to invite the attention of this august House to section 12 of the Sugarcane Control Order, 1966. In the repeal and savings clause, it is mentioned, "with regard to the Sugarcane Control Order 1955 and any order made thereunder, regulating or regimenting the production and supply..." So, this order of 1966 repeals the 1955 order alone. It does not deal with the 1962 Act. The order of 1966 does not repeal the Act of 1962, for obvious reasons that the Central Government must have some power in case of contingency. Now, this order deals with two types of sugar'. It says that the cane growers must be paid by the sugar producer soon after the sugarcane is supplied and payment should be made within 15 days. If the payment is not made, themhe penal provision under section 5 of this Act is to pay the interest. So, payment should be made within 14 days. If not made, the interest would be paid. There are no other penal provisions. There are instances where the private and even the Government mills are not paying the sugarcane prices for years together. For example in our place, Polur, one private sugar mill was ransacked by the sugarcane growers because for years together they have not paid. So, they do not pay sugarcane prices at all. Just like that in Aruna Sugar of South Arcot, they have not paid the prices. There is no penal provision under the Order of 1966. That is why this Act gives special power to the Central Government of any such amendment containing supplementary, incidental and consequential provisions. So, in such a situation, the Central Goverrmient is given additional power to invoke any such thing. But under this Act of 1966 there is no penal provision for not making the payment to the sugarcane growers. I do not think whether any penal provision is there in this Act under which action can be taken. So, in this way, this Act has to be retained and it should not be repealed. As a matter of fact, under Section 6 of this Act there is a provision that when there is no profit or when there is no adequate profit, a person or authority can be

appointed to determine the prices of sugarcane. This power is given under this Act. In our State, Tamil Nadu, there is a claim by all the fanner associations, including all political parties, and they have been making a demand that Rs. 1000 per tonne should be paid. This is a constant demand forever. Even the present Chief Minister also assured that Rs. 1000 will be paid. But, now the Chief Minister has retracted. But, whatever it is, there is a demand to pay Rs. 1000 per tonne. But, this is not being paid. Furthermore what is assured under the Act*... (Interruptions)..*

SHRI KA .RA, SUBBIAN (Tamil Nadu): As far as Tamil Nadu is concerned, we are giving more than all the States. *...(Interruptions)...*

SHRI R. MARGABANDU: You must understand my point. Whatever I am saying is not controversial. *..(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Please conclude. *...(Interruptions)...* Just half an hour back hon. Deputy Chairperson said, "Do not bring your disputes *hsrs."...(Interruptions)...* Please conclude.

SHRI R. MARGABANDU: Why this Act should be sustained, I am attributing reasons for that. So, all the political parties and all the farmer associations have demanded Rs. 1000 per tonne. In Tamil Nadu, they have been paid or not, that is a different matter. What has been assured has not been paid for years together by the private and Government mills. So, penal provisions can be created in the Act of 1966. If the Central Government wants to invoke any power, it can be done only under the Act. My humble submission is that this Act should be retained and it should not be repealed.

SHRJ S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, I would like to say something in connection with the observation made by the hon. Member. *..(Interruptions)...* We have not mentioned it in our election man i festo.... *(Interruptions)...*

SHRI R. MARGABANDU: It was mentioned in your manifesto. .. *(Interruptions)...*

SHRI S. VIDHUTHALAI VIRUMBI: He should go through our manifesto. *...(Interruptions)...* He said that our Chief Minister is retracting. This is a wrong observation.

SHRJ MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Thank you, very

much, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me a chance to speak for the first time before this august House. I personally feel that the provisions of this Bill that has been tabled before this House for repealing, have not been understood properly or have not been administratively implemented. Instead, the hon. Minister concerned has placed this Bill on 14th March, 2000, with an intention to repeal the entire Bill. 1 personally feel, I am afraid, that such a step has been taken, in tune with the recommendations or dispensations of the W.T.O. that is being proved as a disastrous move for our country and for our common people is, when the Sugar Control Order was being exercised, the Government was in a position to determine as to how much of sugarcane would be used for molasses, how much would be used for alcohol and how much sugarcane would be used for other purposes. Now, 'no control' would mean, more control by the very, very big farmers, more control by the monopolists in the agricultural field and, at the same time, 'no control' would mean, further invasion by the multinational corporations to our country. Sir, I very strongly feel that over-commercialisation of agricultural commodities is going to spell a doom for us. It is understood and accepted not only by the Members of the Rajya Sabha, the Members of the Lok Sabha but by any conscious person of this country. We also feel ashamed that, even after a long 52 long years of our independence, unfortunately, almost one-third of the world's hungry population live in this country. The hon. Minister concerned has also mentioned that nearly 33 crores of our population live below the poverty line. Because of the over-commercialisation of agricultural commodities, as practised and encouraged food grains will not be produced. The commodities for the consumption of the people will not be produced. It would only be commercial production that would be encouraged in the agricultural field. I understand and 1 personally believe that even the Government of India, till now, could not give that subsistence and that encouragement to the farmers of this country, but salute to the farmers of this country; they have envisaged ways and means to make this country self-reliant in far as food production is concerned. But, unfortunately, if such measures are taken, if the controls are being repealed like this, if over-commercialisation is encouraged, the sincere breed of the farmers of this country, to whom we should be grateful, even though they are not being patronised by the Government of India, would be discouraged and the self-reliance insofar as food production is concerned, will be completely destroyed. I will just, for the convenience and understanding of the House,

tell you that shrimp production was taken up in a very, very commercial mamier. Sir, millions of acres of land, particularly in the coastal areas of the country, was converted to shrimp production. Agricultural lands were converted into lands where saline water was pushed systematically, perpetually, for shrimp production. At the same time, we also know that whatever shrimp produced here is mostly for export, export to the first-world countries, the developed countries, export to the G-5 nations or the G-7 nations. They consider many points before importing any edible things or any foodstuff For very many reasons they may cancel the orders. Once the orders are cancelled, once the export is hindered, once the export cannot be smoothly advanced, the entire commercial production of shrimp will be in a haywire situation. The land that had been converted into a land for producing shrimp cannot be used for production of foodgrains. So, there will be complete loss of land for the country. The salinated land cannot be used for producing foodgrains. In other words, that cannot be used for production of foodgrains. 1 also doubt that even the ecological balance of this country might have been destroyed to that extent. It can also be attributed to this over-commercial use of the wetland, or, over-commercial use of, what you call the coastal land. Particularly with reference to the Bill, I must say that the Sugarcane Control order is being repealed, or, is being proposed to be repealed. We know, only some months back India had to import sugar from Pakistan. The logic given was that it was cheap. It was imported at the cost of the producers of sugarcane here. Some hon. Members were just now saying that in certain States the sugarcane had to be burnt because there was no market for them. The Government of India had not taken any initiative up till now to utilize the production capacity of sugarcane producers. Instead of that, a Bill is being proposed that the control be removed. So, I personally feel that this Bill should not be repealed like this. You can propose some amendments. You can propose ways and means as to how to use it in the best interest of our country; how to use it in the best interest of the export market of our country; how to use it in the best interest of the common people of our country; how to use it in the best interest of the poverty-stricken people of our country. I would also say that you are trying for over-commercialisation of agricultural commodities, but beware of cheaper competitors. An all-round propaganda has been made as if subsidy to the agriculture is very, very bad; as if subsidy to the agricultural products is very, very bad, it is very, very bad; it should not be there as if the entire money of the Government is being spent

on giving subsidy to agricultural production. It is not a fact, Sir. Even in the advanced developed countries, like the USA, or the G-5 nations, they give sufficient amount of subsidy for agricultural production under different names. They are trying to deceive us by utilizing the office of the WTO. They are trying to deceive our nation and also other developing nations by saying that we should not give any subsidy to th6 agricultural production. All these things are inter-related with this sort of Bill that has been placed before the House. 1 would very sincerely request, through you, the hon. Minister that he should consider ways and means; as has just now been referred to by the hon. Member that the Sugarcane Control (Amendment) Bill, 1996 was not properly utilized, was not properly looked into, was not administratively looked into, and the Government had failed to work or function, where administrative functions were required. I would suggest that ways and means should be found as to how we can best use this control, instead of removing it. By repealing it, 1 repeat, by repealing it we shall only be toeing the line of LPG - liberalisation, privatisation, and globalisation. We shall only be toeing the line of despensetions of the World Trade Organisation. The interest of the entire nation, the interest of the common people of this nation, the interest of the poverty-stricken people of this nation would be at the alter of the WTO. So, on behalf of the people of this nation, I would appeal to the hon. Minister that he should reconsider this. He should give a different shape to this and the Bill may be brought forward again to improve upon the situation so that the required control can be there in the best interest of the people of this country. Thank you. Sir.

श्री शांता कुमार : महोदय, इस बिल पर चर्चा करते समय दो-तीन सवाल उठाए गये हैं। जिनका मै उत्तर देना चाहता हूं। उधर से एक चिंता प्रकट की गयी िक सरकार की तरफ से ऐसी धारणा दी गयी है कि फ्री सेल मेकैनिज़म को समाप्त किया जा रहा है। महोदय, इस बारे में इंडस्ट्री के कुछ लोगों से चर्चा हुई थी कि फ्री सेल का जो मेकैनिज़म है, वह इस ढंग से हो िक उसमें सबके साथ न्याय हो और जो उद्देश्य है- कन्ज्यूमर का लाभ. इंडस्ट्री का लाभ और देश का लाभ- यह सारी चीजें सामने रहें। उस पर विचार करते हुए जिस ढंग से फ्री सेल मकैनिज़म चल रहा था, रिलीज़िज होती थी , उसको रेगुलेट करने की कोशिश की गयी है और इसमें एक महत्पूर्ण निर्णय यह किया गया कि प्रोरेटा, उसमें फ्रीसेल की रिलीज़ को कर दिया गया लेकिन उसको पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है क्योंकि उसमें जैसा उन्होनें कहा हम भी समझते हैं कि यदि उस पर सब प्रकार का नियंत्रण समाप्त कर दिया जाएगा तो चूंकि

उत्पादन अधिक है, भंडार है, वह सारे का सारा भंडार मार्किट में आएगा तो इंडस्ट्री को उससे नुकसान होगा इसलिए यह धारणा ठीक नहीं है। ऐसा निर्णय सरकार ने नहीं किया है। इंडस्ट्री से इस बारे में विचार विर्मश हो रहा था। हमने कहा कि इंडस्ट्रीज एक मत होकर आएं तो अन्य विषयों पर हम लोग विचार कर सकते हैं लेकिन इस संबधं में हमने कोई अंतिम निर्णय नहीं किया है, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। महोदय, इम्पोर्ट की चर्चा हुई। इम्पोर्ट देश के हित में नहीं था इसलिए ज्यों की इम्पोर्ट अधिक होने लगा, उसके बारे में विचार किया गया, और उस पर ड्यूटी 60 प्रतिशत कर दी गयी। 60 प्रतिशत ड्यूटी करने के बाद चीनी का इम्पोर्ट ल्भग बंद है लेकिन सरकार को इस बात काविश्वास है िक उत्पादन अधिक होगा , अगली फसल बहुत बढ़िया आ रही है और इम्पोर्ट की अभी आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार को लगा कि इम्पोर्ट हो सकता है और अधिक हो सकता है तो यथा समय यथा संभव ड्यूटी बढ़ाकर हम देश के अंदर चीनी का इम्पोर्ट नहीं होने देंगे क्योंकि इसी में किसान का, उपभोक्ता का और इंडस्ट्री का हित है। यह मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं। एक और बात एस.डी. फंड के बारे में कही है। शुगर डैवलपमेंट फंड के बारे में नियम है, उनको रिव्यू किया जा रहा है और उसके बारे में जो भी सुझाव आएंगे, अगर माननीय सदस्य कुछ सुझाव देना चाहतें हैं तो उस पर हम विचार करेंगे। इस फंड का ठीक ढंग से इंडस्ट्री के हित मे किस तरह से और अधिक अच्छा उपयोग हो सकता है, इस बात को सामने रखकर जो भी उचित होगा, उस तरह का नियमों में संशोधन किया जाएगा। मैनें कहा कि फ्री सेल की ऐलोकेशन को न्याय संगत कर दिया गया है। एक आरोप उधर से लगाया गया कि उसमें कुछ ऐडिश्नल ऐलोकेशन कुछ मिलों को की गयी है। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि जब से नयी व्यवस्था की है, जब से नयी व्यवस्था मे प्रोरेटा मेकैनिज़म को लाया गया है,उसके बाद से एक भी बोरी की ऐडिश्नल ऐलोकेशन किसी ने कहीं पर नहीं की है। इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। एक बात जरूर है, कई जगह सरकारों ने हमें कहा कि कुछ मिलों की स्थिति ठीक नहीं है, उनके बैंक की जो गांरटी है, वह समाप्त हो गयी है। कहीं पर हमको बताया गया िक आपात स्थिति है – जैसे उड़ीसा की स्थिति थी। इस प्रकार की विशेष परिस्थितयों की बात कई जगह राज्य सरकारों ने हमारे सामने लायी कि इस प्रकार की स्थिति में आप ऐडिश्नल ऐलोकेशन कर दीजिए। उसमें सरकार ने निश्चित निर्णय लिया कि हमने एक बार तय कर दिया है कि ऐडिश्नल ऐलोकेशन किसी को नहीं करेंगे यह निर्णय अंतिम है, यह निर्णय तो नहीं बदला जाएगा। लेकिन यदि कहीं कोई विशेष परिस्थिति आ गयी जिस परिस्थिति के कारण वह मिल किसानों को अदायगी नहीं कर पा रही है, किसान सड़क पर आ गये हैं। लॉ एंड आर्डर की हालत आ गई है, किसान

परेशान है, आपात स्थिति आ गई है, तो उसमें क्या किया जाए ? उसके लिए एक तरीका निकाला गया कि ऐडीशनल ऐलोकेशन नहीं होगी तो नहीं होगी लेकिन ऐसी असाधारण परिस्थिति में राज्य सरकार की रिकमंडेशन पर हम थोड़ी सी ऐडवांस ऐलोकेशन कर देंगे। वह ऐडवांस होगी, ऐडीशनल नहीं होगी । बाद में अगली किश्त में उसको ऐडजस्ट कर लिया जाएगा । तो एक भी बोरी की ऐडिशनल ऐलोकेशन नहीं हुई है । असाधारण या विशेष परिस्थितियों में कई स्थानों पर ... उसके लिए भी निश्चित नियम बनाए गए हैं । उन नियमों के अंदर जो मिल होती है, उस मिल को यदि ऐलोकेशन हुई है तो वह ऐडीशनल नहीं है, केलव ऐडवासं है जो बाद ऐडजस्ट कर ली जाएगी । पी.एम.ओ. का नाम दिया गया लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है । विभाग को, मंत्रालय को प्रधान मंत्री कार्यालय से किसी प्रकार का निर्देश आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी संबधं में वहां से कुछ नहीं कहा गया। इतना ही नहीं कहा गया, अखबारों में तो बहुत कुछ आता है और हर लिखी बात वेदवाक्य नहीं होती । हर छपी बात को सत्य मानकर यदि हम इस जिम्मेदार सदन में आरोप-प्रत्यारोप लगाने की कोशिश करेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा , यह मेरा निवेदन है। अखबारों में तो पता नहीं क्या कुछ छपता है और अखबारों के सारे छपे हुए को हम यहां पर लाएंगे तो हम यहां पर कोई भी काम कर सकते हैं। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। प्रधान मंत्री कार्याल की ओर से इस बारे में कभी कोई बात नहीं कही गई । कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता । हमने सिद्धांत का निर्णय लिया है, उसको निभा रहें है, उसी को निभाएंगे । ऐडीशनल ऐलोकेशन नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, एडवांस हुई है, उसी को निभाएंगे। ऐडीशनल ऐलोकेशन नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, एडवांस हुई है जिसको अगली किश्त में ऐडजस्ट कर लिया जाएगा।

जहां तक इस बिल का सवाल है, इसमें एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि सरकार ने श्री पी.सी.जैन की अध्यक्षता में एक कमीशन मुकर्रर किया था, वह देखने के लिए कि कौन-कौन से ऐसे ऐक्ट हैं जो अब अनावश्यक हो गए है। जिनको रिपील कर दिया जाना चाहिए। उसने भी अपनी रिकमंडेशन में एक ऐक्ट को रिडंडेंट, अनावश्यक समझकर इसको रिपील करने की बात कही थी-इसलिए, क्योंकि शुगरकेन कंट्रोल (ऐडीशनल पॉवर्स) ऐक्ट, 1962 सेंट्रल गवर्नमेंट को शुगर कंट्रोल ऑर्डर, 1955 को अमेंड करने के लिए ऐम्पॉवर करता था । उसी में जब वह आवश्यक नहीं रहा तो इसमें इसकी कोई आवयकता नहीं है।

यहां पर कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई है कि बहुत सी बातों पर हम अपना नियंत्रण कैसे रख सकेंगे ? तो मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं िक शगुरकेन कंट्रोल ऑर्डर, 1966 है जिसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। शुगर कंट्रोल ऑर्डर, 1966

है जिसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है । लेवी शुगर सप्लाई कंट्रोल ऑर्डर, 1979 है जिसके द्वारा इन सारी बातों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह जो अमेंडमेंट हैं, यह जो एक्ट है, यह जो अनावश्यक है, उसको रिपील करने के लिए है । बाकी जो बातें मैनें कही है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन सारे सुझावों पर सरकार विचार करेगी । मैं निवेदन करूंगा कि क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं रही है, इसलिए सदन इसको रिपील करने केलिए पास करें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): The question is:

"That the Bill to repeal the Sugarcane Control (Additional Powers) Act, 1962, be taken into consideration."

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री शांता कुमार : मैं अनुरोध करता हूं कि :
इस विधेयक को पारित किया जाए ।

The question was put and the motion was adopted

STATEMENT BY MINISTER

Increase in Prices of Certain Petroleum Products

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल) : रूपया उठा भी लिया, वह हजम भी हो गया, अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा ? सरकार अब यह स्टेटमेंट प्राइस उज्ज्वल करने के लिए लाई हैं ? सब बातचीज करने के लिए तैयार हैं । और एक डिसकशन मंहगाई परकिया जाए । पैट्रोलियम और कैरोसिन वाली जिस सरकार ने यह बीच में किया है ।, Otherwise a piecemeal discussion will not work. It is an attempt to take the wind out of the people's discontent.

जब सदन चल रहा था तब प्राइस नहीं बढ़ाए बल्कि इन्टर सेंशन में बढ़ाए हैं ।